भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1873
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का डेटाबेस

1873: डॉ. संबित पात्रा

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र की समितियों का एकीकृत डाटाबेस बनाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस डाटाबेस में शामिल समितियों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है;
(घ) विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए डाटाबेस कब तक तैयार हो जाएगा;
(ङ) क्या व्यय होने वाली संभावित धनराशि का कोई आकलन किया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख) जी हाँ, मान्यवर। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) विकसित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों के आंकड़ो को डेटाबेस में प्रविष्ट किया गया है।

एनसीडी को तीन चरणों में विकसित किया गया है। फरवरी 2023 में पूरा हुए चरण- । में कृषि, डेयरी और मात्स्यिकी में लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों को जिला पंजीयक कार्यालयों और AICTE के 500 स्थानीय इंटर्नों की मदद से मानचित्रण किया गया । चरण- ॥ में राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों और राज्य एवं जिला स्तरों के साथ उनके लिंकेजों का मानचित्रण करके विभिन्न सहकारी बैंकों और परिसंघों से आंकड़े एकत्र किए गए। मई 2023 में शुरू किए गए चरण- ॥। में डेटाबेस को अन्य क्षेत्रों की 5.3 लाख से अधिक सहकारी समितियों तक विस्तारित किया गया, जिसमें लगभग सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित सहकारी समितियों के कार्यालयों के माध्यम से डेटा प्रविष्टियां पूरी की गईं।

(ग) एनसीडी पोर्टल के अनुसार, दिनांक 01.03.2025 तक सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-2** में संलग्न है।

(घ) एनसीडी के अनुसार वर्तमान में 8 लाख से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं, जिनसे लगभग 30 करोड़ सदस्य जुड़े हैं। यह डेटाबेस अब https://cooperatives.gov.in URL पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) एनसीडी के विकास और रख-रखाव कार्य के लिए सहकारी शिक्षा निधि (सीईएफ) से अब तक लगभग 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

राज्यवार सहकारी समितियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	समितियों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2230
2	आंध्र प्रदेश	17884
3	अरुणाचल प्रदेश	1302
4	असम	11304
5	बिहार	26389
6	चंडीगढ़	476
7	छत्तीसगढ	10973
8	दिल्ली	5944
9	गोवा	5504
10	गुजरात	83647
11	हरियाणा	33286
12	हिमाचल प्रदेश	5431
13	जम्मू और कश्मीर	10122
14	झारखंड	11675
15	कर्नाटक	45205
16	केरल	16031
17	लद्दाख	273
18	लक्षद्वीप	43
19	मध्य प्रदेश	53753
20	महाराष्ट्र	222798
21	मणिपुर	11457
22	मेघालय	3135
23	मिजोरम	1289
24	नगालैंड	8022
25	ओडिशा	7588
26	पुदुचेरी	461
27	पंजाब	19236
28	राजस्थान	40860
29	सिक्किम	3798
30	तमिलनाडु	22395
31	तेलंगाना	60515
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	566
33	त्रिपुरा	3207
34	उत्तर प्रदेश	44910
35	उत्तराखंड	5570
36	पश्चिम बंगाल	31779
कुल		**829058**

स्त्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 01.03.2025 तक

अनुलग्नक-2

सहकारी समितियों की क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं.	क्षेत्र	समितियों की संख्या
1	कृषि एवं संबद्ध सहकारी	27511
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी	23492
3	मधुमक्खी पालन सहकारी	331
4	उपभोक्ता सहकारी	22803
5	ऋण एवं बचत समिति	82902
6	डेयरी सहकारी	147641
7	शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सहकारी समितियां	1256
8	किसान सेवा समितियां (एफएसएस)	541
9	मत्स्य पालन सहकारी	26271
10	हस्तशिल्प सहकारी	5186
11	हथकरघा वस्त्र एवं बुनकर सहकारी	19553
12	आवास सहकारी समिति	193575
13	जूट एवं कॉयर सहकारी	69
14	खादी ग्रामोद्योग	13
15	श्रम सहकारी	45953
16	वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति (लैम्प्स)	5629
17	पशुधन एवं मुर्गीपालन सहकारी	16784
18	विपणन सहकारी समिति	9831
19	विविध ऋण सहकारी समिति	7124
20	विविध गैर ऋण	33884
21	बहुउद्देशीय सहकारी	20841
22	प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स)	100739
23	रेशम उत्पादन सहकारी	511
24	सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक सहकारी	2387
25	चीनी मिल सहकारी	290
26	पर्यटन सहकारी	558
27	परिवहन सहकारी	4233
28	आदिवासी-एससी/एसटी सहकारी	1768
29	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1442
30	महिला कल्याण सहकारी समिति	25965
कुल		**829058**

स्त्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 01.03.2025 तक